

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा (म0प्र0)

क्रमांक-Q-46 / जि0न्या0छिं0 / 2020

छिंदवाडा दिनांक 17.01.2021

विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 17.01.2021 को पारित)

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक ए/113/जबलपुर दिनांक 15.01.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा कुटुम्ब न्यायालयों में दिनांक 18 जनवरी 2021 से समस्त प्रकृति के मामलों में नियमित रूप से भौतिक सुनवाई प्रारंभ किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः जिला मुख्यालय, छिंदवाडा एवं उसकी समस्त तहसील न्यायालयों में न्यायालयीन कार्य के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1)- पिछले एक सप्ताह के आकड़ों के अनुसार छिंदवाडा जिले में प्रतिदिन कोविड-19 के मरीजों की संख्या 10 से कम रही है, इस कारण जिले में समस्त प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई सभी न्यायालयों में भौतिक के साथ-साथ व्ही0सी0 के माध्यम से भी की जायेगी।

(2)- मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट रूल्स, 1961 के नियम 5 तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समस्त न्यायालय अपने नियमित समय पर कार्य करेंगे।

(3)- कोविड-19 के केस बढ़ने की स्थिति में भौतिक सुनवाई के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर व्ही0सी0 के माध्यम से सुनवाई के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

(4)- प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रतिदिन सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरण की कॉज लिस्ट तैयार कर सूचना पटल पर चरपा कर कॉज लिस्ट अनुसार प्रकरण की सुनवाई इस प्रकार करेंगे कि न्यायालय में भीड़ न लगे। काज लिस्ट में लंच के पूर्व तथा लंच के बाद लिये जाने वाले प्रकरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(5)- साक्षीगण, पक्षकार एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति आदेश पत्रिका में अभिलिखित की जायेगी, किंतु जहाँ कानूनन अनिवार्य हों, वहाँ उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

(6)- प्रथम रिमाण्ड के समय अभियुक्त की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, उसके उपरांत व्ही0सी0 के माध्यम से रिमाण्ड दिया जायेगा। विचाराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति जब तक अनिवार्य न हो, रिमाण्ड के माध्यम से की जायेगी।

(7)- समस्त न्यायालय सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर सी0आई0एस0 एन0सी0-3.2 के माध्यम से समंस जारी करायेंगे एवं प्रकरणों को प्रतिदिन अपडेट करेंगे।

(8)- जिले के समस्त न्यायालयों में अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी, पक्षकार एवं स्टाफ के न्यायालय में अंदर आने-जाने के रास्ते इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि भीड़ एकत्रित न हो, यह कार्य संक्रमण की रोकथाम एवं निगरानी हेतु गठित कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

(9)- जिला मुख्यालय छिंदवाडा या इसकी तहसील न्यायालयों के क्षेत्र में कर्फ्यू, लॉक डाउन/कंटेन्मेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के न्यायालय का कार्य बंद रहेगा, किंतु अत्यावश्यक प्रकृति के मामले में व्ही0सी0 के माध्यम से कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 को सूचित करते हुये जारी रहेगी।

(10)- यह सुनिश्चित किया जाये कि केवल ऐसे पक्षकार व अधिवक्तागण को ही न्यायालयों में प्रवेश दिया जाये, जिनके मामलों की सुनवाई उस दिन नियत हो। इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर न्यायालयीन स्टाफ की व्यवस्था की जाये।

(11)- न्यायालय में प्रकरण एक के बाद एक सुने जायेंगे, प्रत्येक सुनवाई के मध्य 2 मिनट का इस्तेमाल सेनेटाईज किये जाने हेतु किया जायेगा।

(12)- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन एवं फोटोकॉपी दुकान आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।

(13)- पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षियों को प्रवेश दिया जाये, जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगाई गई हो, अन्य पक्षकार/अधिवक्तागण सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अपने प्रकरण की प्रतीक्षा करेंगे।

(14)– न्यायालय कक्ष में कुर्सी एवं बेंचों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्थित करना पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

(15)– न्यायालय कक्ष के बाहर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाये, जिससे कॉज लिस्ट अनुसार सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरण डिस्प्ले बोर्ड में अधिवक्तागण एवं पक्षकार की सुविधा हेतु प्रदर्शित हो।

(16)– न्यायालय परिसर में किसी प्रकार का आयोजन अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(17)– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा एस0ओ0पी0 दिनांक 15.01.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने एवं कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	उप प्रशासनिक अधिकारी
1	श्री राजीव कुमार अयाची, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) छिंदवाड़ा	श्री विजय सिंह गौतम	श्री चत्तूलाल यादव

तहसील न्यायालय अमरवाड़ा

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	श्री राजेंद्र नेमा, अधिवक्ता	वासू वर्मा

तहसील न्यायालय सौंसर

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	श्री एस0डी0 राउत, अधिवक्ता	श्री सुरेश विश्वकर्मा

तहसील न्यायालय पांढुर्णा

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्री महेंद्र सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	श्री कुंदनलाल पराडकर, अधिवक्ता	श्री विट्ठल कवलाते

तहसील न्यायालय जुन्नारदेव

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्रीमती सोमप्रभा चौहान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	श्री धर्मेन्द्र राव, अधिवक्ता	श्री रफीक खान

तहसील न्यायालय परासिया

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्री अल्लमश रहमान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	श्याम कुमार साहू, अधिवक्ता	श्री अजय शिवारे

तहसील न्यायालय चौरई

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्री प्रदीप कुमार बरकड़े, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	सेवकराम वर्मा, अधिवक्ता	श्री अमित जैन

तहसील न्यायालय हरई

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नायब नाजिर
1	श्री कपिल बौरासी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	बार अध्यक्ष, अमरवाड़ा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि	श्री लखनलाल दुबे

तहसील न्यायालय तामिया

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बार अध्यक्ष	नाजिर/नायब नाजिर
1	श्री प्रतीक सिंह तोमर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	बार अध्यक्ष, जुन्नारदेव द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि	श्री नाथूराम धुर्वे

(18)– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, सेनेटाईजर, साफ-सफाई, न्यायालय में उपस्थिति, बीमारी के लक्षण आदि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा दिनांक 15.01.2021 को जारी एस0ओ0पी0 (संलग्न) में दिये गये समस्त निर्देशों के साथ-साथ बिन्दु क्रमांक 11 से 36 तक दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु गठित की गई उपरोक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एस0ओ0पी0 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(19)– केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा।

(20)– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस0ओ0पी0 दिनांक 15.01.2021 में न्यायिक अधिकारियों के लिये दिनांक 18.01.2021 से 50 प्रतिशत यूनिट दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं, जिसका पालन किया जाना समस्त न्यायिक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

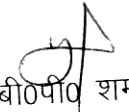

(बी0पी0 शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपि:–

- 1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3– अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील– सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5– जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6– पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

- 7- आयुक्त, नगर निगम, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 11- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।
- 12- कोविड-19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 14- प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 15- कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 16- प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(बी.पी. शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// SOP FOR SUBORDINATE COURTS //

No./ A/113/

Jabalpur dated 15/01/2021

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start regular physical functioning in the Subordinate Courts including Family Courts in respect of all category of cases w.e.f. 18.01.2021.

- (1) All types of cases will be taken up by the Courts subject to the directions issued by the District & Sessions Judge.
- (2) The District & Sessions Judge will have discretion to regulate the physical functioning in the Court including the nature and categories of cases, number of cases and timings of sitting of Judges depending upon the prevailing circumstances and effect of Covid-19 in the concerned district.
- (3) Depending upon the seriousness of Covid-19 effect, the District & Sessions Judge will have an option to switch to limited virtual hearing through video conferencing/mixed functioning through physical mode and video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.
- (4) The District & Sessions Judges will take immediate steps for installing the plastic curtain between the Judges/Reader, Staff AND Advocates/ litigants in each functional court room.

- (5) The District & Sessions Judge will ensure the publication of daily cause list showing the matter listed before different courts and the court concerned will take up the cases as per serial order in the daily cause list. The cause list will also disclose the cases to be taken up in pre-lunch session and post-lunch session.
- (6) The courts shall usually function as per timings of the courts specified in Rules and Orders, except at places where lockdown/shutdown is imposed or containment zone declared by the competent authority.
- (7) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files, and their signatures would not be taken on order sheet, statements (Except where law requires) to prevent the spread of Corona virus, till further orders.
- (8) Production of the accused before the court may be, unless specifically directed otherwise for any reason, accepted by video conferencing. However, the accused shall be required to be produced before the Magistrate for remand in the first instance. But, subsequent remand may be granted by video conferencing.
- (9) All the Judicial Officers are hereby impressed upon for the use of service of summons through the message by using the facility in the Software CIS NC 3.2 in addition to normal mode of service, which has been provided for in order to facilitate service of summons.

- (10) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.
- (11) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.
- (12) Persons consuming liquor, pan, gutkha or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.
- (13) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover, covering nose and mouth (including at the time of argument and tendering evidence). Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without wearing proper face mask.
- (14) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.

- (15) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.
- (16) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association with intimation to the District Judge.
- (17) Working of the Subordinate Courts / Family Courts in the State shall remain suspended in areas where curfew / lockdown / containment area has been declared by the competent authority. However, the court shall take up urgent matters and the intimation of the situation be communicated to the High Court.
- (18) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the restricted entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.
- (19) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding.
- (20) Bar Rooms, Advocates' Chamber, Bar Library shall remain open subject to adherence of all the safety norms. The Bar President shall

observe safety norms and ensure sanitization as well as limited entry through the Bar Room(s) to prevent crowding.

- (21) Proper sanitization of entire premises i.e. Court Rooms, chamber of Presiding Officer, offices, toilets and place of common use must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.
- (22) The District Judges should ensure installation of adequate numbers of wash basins in addition to arrangement of sanitizer so that the visitors/lawyers/staffs can properly sanitize their hands before entering the Court premises/complexes.
- (23) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.
- (24) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders. In no case at a time more than 10 persons (advocate / witness / party / accused) (subject to availability of space) will be allowed in a Court Room. Entry of number of persons in the Court Room will be as per the instructions issued by the concerning District Judge, keeping in view the space available in the Court Room. Cases shall be heard consecutively i.e.

one by one and a break of 2 minutes shall be given for proper sanitization before starting hearing of new case.

- (25) The Chairs/Benches in the Court Hall should be suitably arranged keeping in mind the social distancing norms. The sitting arrangement of staff in the Court and Offices shall also be made compliant to social distancing norms.
- (26) At no circumstances the Court Hall or Court Varanda / common passages / corridors or Court premises shall be crowded. Congregation in any form is to be prevented.
- (27) The display boards shall be functional and the cause list be displayed for convenience and information to all stakeholders.
- (28) Orders/Judgments passed by the Court and next date of cases shall be uploaded on the website of the concerning District at the earliest.
- (29) In order to avoid physical contact, the drop box system to receive applications / petitions etc. in the Court for which filing counter is not provided, be adopted by respective Courts, in such matters the party concern / his advocate shall mention his e-mail ID and mobile number on applications / petitions etc.
- (30) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.

- (31) As Government advisory has required restricted movements for persons aged 65 years and above, learned Advocates / Senior Advocates aged 65 years and above are requested to exercise due caution / avoid physical appearance in the Courts.
- (32) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and Deputy Administrative Officer, wherever available / one senior court staff, shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions. The Committee shall report the District Judge.
- (33) No function or any other event shall be permitted inside the Court premises.
- (34) District & Sessions Judges are authorized to make any suitable changes according to the prevailing situation of any court in his jurisdiction for smooth functioning of courts and also for management for preventing the spread of Corona Virus in the matter of entry and sitting of the advocates, litigants etc. in court premises, under intimation to the High Court.
- (35) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.
- (36) If any advocate(s) or litigant(s) is found violating the above guidelines, the District Judge / Principal Judge shall bring it to the

notice of the Bar Council of Madhya Pradesh and respective Bar Association(s) under intimation to the High Court and may take such action as he/she deems fit and proper.

- (37) From the date of implementation of this Circular, the Units criteria shall be relaxed to 50% of the prescribed Units till further order / modification.
- (38) The Units criteria relaxed as per Circular no. A/2874, dated 03.12.2020 shall remain extended upto implementation of this Circular.


15.1.21
(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL